भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3774

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

नए उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्यों को प्रोत्साहन

†3774. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना या मौजूदा संस्थानों का विस्तार करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजना के तहत संस्थानों के चयन के लिए मानदंड क्या हैं और प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों की प्रकृति क्या है;
(घ) इसके कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है;
(ङ.) इस प्रयोजन के लिए तमिलनाडु को कितना बजट आवंटित किया गया है और इन संस्थानों की स्थापना या विस्तार का समर्थन करने के लिए वित्त पोषण तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
(च) वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार और उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में उक्त योजना का प्रभाव क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का क्रियान्वयन कर रहा है, जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य विशेष राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तपोषित करना है ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने शैक्षिक रूप से वंचित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 12926.10 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण की जून 2023 में शुरुआत की है। पीएम-उषा के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। फोकस जिलों की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्न सकल नामांकन अनुपात, जेंडर समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जिले आदि शामिल हैं।

इस योजना में विभिन्न घटकों जैसे बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ बनाने हेतु अनुदान (जीएसयू), कॉलेजों को सुदृढ़ बनाने हेतु अनुदान (जीएससी), नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी) और लैंगिक समावेशिता एवं समानता पहलों (जीआईईआई) के तहत सहायता के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता में सुधार की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत, विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 8178.71 करोड़ रुपए की राशि के साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 615 इकाइयों को स्वीकृति दी गई है।

वर्ष 2013 में इस योजना की शुरुआत के बाद से तमिलनाडु राज्य में विभिन्न घटकों के अंतर्गत 526 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ कुल 99 इकाईयां अनुमोदित की गई हैं। इसमें से अब तक, राज्य को 416.13 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

*****